12.40 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR RECOMMENCEMENT OF EXPORT OPERATIONS FROM ALLEPPY PORT IN KERALA.

SHRI B. K. NAIR (Quilon): Alleppey Port on the West Coast of Kerala has been remaining unused for several months now owing to lack of proper attention to maintenance work. But now, following prolonged agitation by the unemployed Port workers and the starving members of their families numbering several thousands and outcry from the public, the requisite facilities have been restored and essential repairs and renovatiln carried out. A few Barges needed for taking Cargo to and from the ships out in the sea have also been acquired and put in service.

Under these circumstances, I have to appeal to the Goverment of India to make arrangements for recommencing export and import operations at this Port, not only means to save the workers from misery but also to relieve congestion and ease the situation in other Ports like Cochin and Bombay. With the outbreak of monsoon just only a few weeks away. during which a Port has to remain closed, it is hoped that urgent attention will be paid to this matter even if it means diversion of at least few ships within the days to come.

(ii) NEED FOR INCREASED ASSISTANCE TO RAJASTHAN GOVERNMENT TO MEET SEVERE DROUGHT IN THE STATE

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राजस्थान में 26 जिलों में से 25 जिले सूखाग्रस्त हैं जिसके कारण इन जिलों के 26 हजार से भी अधिक गांवों की लगभग डेढ़ करोड़ जनसंख्या इस भीषण अकाल का सामना कर रही है । इनमें से कुछ क्षेत्र तो पिछले तीन-चार वर्षों से सूखे की विभीषिका से पीड़ित हैं ।

12.42 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अकाल राहत कार्य भी धीमी गति से चल रहा है । गांवों में तालाब, कुएं आदि का पानी सूख गया और यदि कुओं में पानी है भी तो वह काफी नीचे हैं । जिन क्षेत्रों में नलकूप लगे हुए हैं उनमें से भी कुछ नलकूपों की हालत खस्ता हैं । क्योंकि इन नलकूपो को समुचित मात्रा में बिजली प्राप्त नहीं हो रही है या फिर इन नलकूपों के समुचित रखरखाव के अभाव में ये बेकार हो रहे हैं जिससे स्थानीय जनता काफी प्रभावित है ।

लोगों को पीने का पानी गांवों से पांच किलोमीटर से भी अधिक दूरी से लाना पड़ रहा है जिसके लिए लोगों को एक घड़े पानी के लिए दस रुपये तक भी देने पड़ते हैं जबकि इन क्षेत्रों में कुओं को अधिक गहरा करके और नलकूपों का समुचित प्रयोग करके प्रभावित क्षेत्रों की जनता को पीने का पानी आसानी से सुलभ कराया जा सकता है ।

अगर यही हालत रही तो आगामी गर्मियों में स्थिति और भी बद से बदतर हो जायेगी । जिन जिलों में पिछले तीन-चार वर्षों से बराबर अकाल पड़ रहा है वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चली है । ये लोग अपने यहां रोजगार के अवसर के कोई आसार नजर न आने के कारण मजबूरन रोजगार की तलाश में पड़ौसी राज्यों को पलायन करने लगे हैं । राज्य सरकार इस स्थिति के पूर्ण रुपेण निपटने में विफल रही है और पूरा प्रदेश अकालग्रस्तता के कारण त्राहि-त्राहि करने लगा है ।

अगर हालत यही रही तो आगामी गर्मियों में स्थिति और भी बद से बदतर

हो जायेगी । इसलिए सरकार को अविलम्ब अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सर्वप्रथम पीने का पानी, पशुओं के लिए चारा और रोजगार के अधिक अवसर सुलभ कराने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, कुओं, पटवार घरों, स्कूल भवनों, आयुर्वेदिक और पशु चिकित्सालयों के निर्माण-वन और चारागाह विकास, पेयजल व्यवस्था और सहायक व्यवसायों के प्रशिक्षण आदि कार्य हाथ में लेकर इस समस्या के हल के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की जनता को रोजगार के अधिक अवसर सुलभ कराये जाएं । अगर समय रहते सूखाग्रस्त स्थिति को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये गये तो स्थानीय जनता में यह आशंका व्यक्त की जाने लगी है कि प्रदेश में बिहार की भांति सूखे की स्थिति यथावत् बनी रहेगी ।

मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे राजस्थान की अकालग्रस्त स्थिति को हल करने के लिए राज्य सरकार को अधिक अनुदान प्रदान करें जिससे वह अपने प्रदेश में इस विकट समस्या को सुलझाने के लिए हल ढूंढने में गति ला सके और लोगों में विश्वास जगा सके ।

(iii) NON-AVAILABILITY OF COOKING GAS IN RANIGANJ AREA

SHRI KRISHAN CHANDRA HALDER (Durgapur): Under Rule 377, I am making a statement.

Ranigaj area is not getting cooking gas supply since October, 1980 causing acute hardship and distress to gas consumers. Raniganj depends entirely on Hindusthan Petroleum supply. Several representations, already made, draw no attention of the authorities as well as Minister of Petroleum and Chemicals about the non-availability of cooking gas in Raniganj area.

Under the circumstances I urge upon the Government to take immediate steps for restoration of Hindusthan Petroleum supply and also additional supply by Indian Oil Corporation to the Raniganj area.

(iv) STEPS FOR REHABILITATION OF PEOPLE AFTER THEIR EVICTION UNDER THE LAND ACQUISITION ACT IN TAMIL NADU

DR. V. KULANDAIVELU (Chidambaram). Under Rule 377, I am making a statement.

In the interest of the public I would like to make a submission on the floor of the House that an adequate care must be ensured in rehabilitation of the people when they are evicted from a place in the Land Acquisition Act.

I refer to the prevailing atmosphere at Neyveli Complex in Tamil Nadu. The Tamil Nadu State Govt. has just now acquired lands for NLC Project expansion scheme and evicting the villagers under Land Acquisition Act, and the process is continuing for a better cause of a major project. The people who surrender lands and household properties to the NLC Ltd. in the rural areas express their dis-satisfaction of being neglected and poorly attended by the authorities in rehabilitation measures. They also claim for job opportunities in the NLC, Ltd. for each family involved in the Land Acquisition and reasonable higher fixation of remuneration for their land and household properties on the grounds of being in the adjoining Town areas.

When we are anxious to see our country to prosper in rapid industrialisation and early execution of project schemes should not fail to realise the gravity of Psychological trauma caused to the meagre section the poor villagers when their lands and household properties are acquired and subjected for eviction, I restate that care must be ensured in rehabilitation. If it is not of mere exaggeration that the people are invariably under the misery of being